

ARBIT



Who were the Hessians?

The Hessians were supposed to quickly end the American Revolution. Instead, they endured years of battles and suffered thousands of casualties

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

Rashtradoot

How Bagore in Madhya Pradesh proves that Hinduism existed long before recorded history

The Hindu in Ancient History

epaper.rashtradoot.com

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर उतरे लोग

जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट्स, छात्रों और विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर सभी को रोका

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 25 सितंबर। चुनाव आयोग के कथित गलत कार्यों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन-एसआईआर) से संबंधित को लेकर विवाद अब चुनाव आयोग की फाइलों से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। शुक्रवार को जंतर-मंतर पर ऐक्टिविस्ट्स छात्रों और राजनीतिक नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तो वहां भारी बैरिकेडिंग कर दी।

शुक्रवार को पुलिस की कार्रवाई ने निर्धारित प्रदर्शन स्थल को सुरक्षा घेरे में बदल दिया। चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया, जबकि वामपंथी नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के पीछे रोक दिया गया।

- सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर संबंधी उनके मनमाने फैसलों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है. देश भर से इस्तीफे की मांग उठ रही है।
- इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों को चुनौती दी गई है। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने अधिवक्ता चांद कुंरैशी के जरिए दायर की।
- एक अन्य अधिवक्ता, बृजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी से सीईसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी और सीईसी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों ने “द ट्रिब्यून” को बताया कि सी पी आई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, ऐक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एआईएसए (आईसा) की राष्ट्रीय

है। तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर सामने आई कथित आपत्तियों ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने या दोबारा शामिल करने जैसे फैसलों पर आखिरकार नियंत्रण किसका है। मतदाता सूची के डेटा पर केन्द्रीकृत नियंत्रण और ऐसी घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है, जहां अधिकारियों के फैसले सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज नहीं किए जा सके।

इस अभियान को तब और गति मिली, जब सीजेपी ने कुमार से 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि अगर उन्होंने पद नहीं छोड़ा तो देशभर में आंदोलन तथा जंतर-मंतर पर फिर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

इस बीच, प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार के इस्तीफे की सीजेपी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने मतदाता सूची के एस आई आर के दौरान पूरे देश में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के प्रस्ताव पर वि.सभा में हंगामा

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में राज्य विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसके

- सु.मंत्री उमर ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव रखा, भाजपा ने हंगामा किया और प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं।

बाद सदन में भारी हंगामा और धक्का-मुक्की हुई तथा भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव को प्रतियां फाड़ दी।

प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहले पारित किए गए प्रस्तावों, जिसमें 2000 में पारित जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता का प्रस्ताव भी शामिल था, का उल्लेख किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया।

भाजपा सदस्य सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करते हुए प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं। सत्तारूढ़ नेशनल काँग्रेस के सदस्यों ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है, “26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार को “स्पेशल प्रिविलेज” ?

ज्ञानेश कुमार की पुत्री और नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेघा रुपम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष तरजीह दिए जाने पर वकीलों ने विरोध जताया

- मेघा रुपम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली युनिवर्सिटी की छात्र नेता आकृति चौधरी को नेशनल सिव्जुरिटी एक्ट में गिरफ्तार करने के फैसले को रद्द कर दिया था और आकृति को 5 लाख रु. का हर्जाना देने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यह राशि मेघा के वेतन से वसूली जाए।
- मेघा की याचिका की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेघा से वसूली के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी।

आयोजन स्थल की उपलब्धता, वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्रम और प्राकृतिक परिस्थितियों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में भी इसी तरह के कार्यक्रम पहले स्थगित किए जा चुके हैं।

हालांकि कार्यक्रमों के स्थगित होने के समय ने इस मामले की ओर ज्यादा ध्यान खींचा है। यह फैसला “इंडियन एक्सप्रेस” की एक जांच रिपोर्ट के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव

आयुक्त सुखबीर सिंह संघू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की थी। उनकी आपत्तियां, जो 2025 के अंत से अगस्त 2026 के बीच दर्ज की गईं और अक्सर ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गईं, मतदाता सुविचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीज/एसआईआर) से जुड़ी थीं। इनमें नए मतदाताओं को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ज्ञानेश कुमार का मेरठ और वाराणसी दौरा स्थगित

चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया, दौरा रद्द होने का संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े हालिया विवाद से नहीं है

- जाल खंभाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 25 सितम्बर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मेरठ और वाराणसी का दौरा स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि यह फैसला 21 सितंबर को लिया गया था और इसका चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों से कोई संबंध नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दोनों शहरों के जिला अधिकारियों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के दौरे को व्यवस्थित और स्थानीय कारणों के साथ-साथ उनके

- उत्तर प्रदेश में मेरठ और वाराणसी में ज्ञानेश कुमार नए वोटर्स के साथ संवाद करने वाले थे।
- सूत्रों ने बताया कि सीईसी के उत्तराखंड, हिमाचल व लद्दाख के दौरे को भी स्थगित कर दिया गया है।

आधिकारिक कार्यक्रम में हुए बदलावों के कारण रीशिड्यूल किया गया है।

आयोग के सूत्रों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के दौरे भी स्थगित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का कार्यक्रम पर्यटन सीजन और परीक्षाओं के कारण टाल दिया गया था।

उत्तराखंड में युवाओं के साथ होने वाली बातचीत का कार्यक्रम

जयपुर, जोधपुर, कोटा में भाजपा के महापौर बने

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 25 सितम्बर। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में भाजपा के महापौर बने हैं। शुक्रवार को इन तीनों निगमों में पार्षदों के मतदान के बाद ये परिणाम सामने आए। जयपुर में सुनील कोटारी, जोधपुर में प्रसन्नचंद मेहता और कोटा में अनुसुइया गोस्वामी

- तीनों स्थानों में भाजपा ने अपने निर्वाचित पार्षदों के अलावा भी वोट हासिल किये।

महापौर बनीं। तीनों ही नगर निगम में भाजपा को चुनाव में जीते पार्टी के पार्षदों से ज्यादा वोट मिले। कोटा में तो कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग तक कर दी। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी राजेन्द्र सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा।

देखा जाए तो इस बार निकाय चुनाव में प्रदेश के 10 नगर निगमों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के खिलाफ असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं भारत सरकार में

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका के व्यापार प्रतिबंध और टैरिफ तथा ग्राहम एक्ट, अमेरिका की अन्य देशों पर दबाव डालने की रणनीति है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 25 सितंबर। ट्रंप प्रशासन के प्रति अब तक अपनाए गए एक तरह से नतमस्तक रवैये से अलग एक दुर्लभ स्वतंत्र रुख जाहिर करते हुए भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (सी ई ए) वी. अनंत नागेश्वरन ने आज अमेरिका के व्यापार प्रतिबंधों, टैरिफ और ग्राहम एक्ट को लगातार दबाव की एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देशों को प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक गुटों में से किसी एक के साथ खड़े होने के लिए मजबूर करना है।

सी ई ए ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से दो या तीन

- नागेश्वरन ने साफ कहा कि भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकार व रणनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से भारत किसी एक गुट के साथ नहीं जुड़ सकता है।
- नागेश्वरन ने कहा कि व्यापार को हथियार बना दिया गया है और इसका इस्तेमाल बड़े देश दूसरे देशों को धमकाने के लिए कर रहे हैं।

प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच आकार ले सकती हैं, जिसमें भू-राजनीति (जियोपॉलिटिक्स) का व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा पर प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका के साथ अस्थिर संबंधों, वैश्विक ऊर्जा की

संबंधों में आई खटास को स्वीकार किया है। अब तक नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी के डर से एक आज्ञाकारी साझेदार की भूमिका निभाती रही है।

सी ई ए के अनुसार, ग्राहम एक्ट और व्यापार प्रतिबंधों जैसे कदमों को देशों पर रणनीतिक विकल्प चुनने के बढते दबाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ग्राहम एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जो रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं।

नागेश्वरन ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकार और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से देश के लिए किसी एक भू-राजनीतिक गुट के साथ पूरी तरह जुड़ना मुश्किल है।

हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की भी आर्थिक और नीतिगत कोमत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल आज प्रतापगढ़, उदयपुर जायेंगे

- जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को प्रतापगढ़ और उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत, मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसके
- वे विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण करेंगे तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

साथ ही वे जनसभा को संबोधित करने के अलावा, भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रतापगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 12:40 बजे वे प्रतापगढ़ पहुंचकर दोपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना करेंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग संचालक द्वारा विरोधी अधिवक्ताओं को जान से मारने की धमकी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

जयपुर के गोपालपुरा बाईपास से गैर कानूनी कोचिंग सेंटर को हटाने की पैरवी नहीं करने के लिए धमकी दी गई थी

- वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने अदालत में कहा कि, “जयपुर के कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर ने हमें जान से मारने की धमकी दी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी नहीं करने के लिए धमकाया।”
- इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी व मुख्य सचिव को 24 सितंबर को हाजिर होकर जवाब देने के आदेश दिए थे, परंतु राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने कहा कि डीजीपी ने 24 घंटे में इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी।
- वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन देने के 3 दिन बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा।”

नहीं की गई? उधर इस प्रकरण में राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि, उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से फोन पर बात कर ली है, डीजीपी ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। जिस पर अदालत ने डीजीपी व मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति रोकते हुए मामले की सुनवाई 23 नवंबर तय कर दी, परंतु हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के 3 दिन बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने अदालत में यह भी बताया कि, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसके बाद

बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जायेगा।

गौरतलब है कि गत 11 सितंबर को 10-वीं स्कीम विकास समिति के महासचिव गोपाल कुमार अग्रवाल ने शिप्रापथ थाने में कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराया था। उन्होंने एफ.आई.आर. में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेशों के बाद जेडीए ने 10 सितंबर को गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर पर जब कार्रवाई शुरू की तो कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर ने उन्हें फोन कर भद्दी गालियां देते हुए धमकाया। आरोप है कि डागुर ने धमकी दी कि अगर ली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट से केस वापस नहीं लिया तो गोपाल अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल और राजदीपक रस्तोगी को जान से मरवा दिया जाएगा। धमकी के दौरान कथित तौर पर डागुर ने अपनी राजनीतिक पहुंच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा आज रिटायर होंगे

जयपुर, 25 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश व एक्टिंग सीजे रहे संजीव प्रकाश शर्मा शनिवार को रिटायर हो रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले जस्टिस शर्मा हाईकोर्ट परिसर

- बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व वकीलों ने माला, साफा पहनाकर सम्मान किया।

में वकीलों के बीच पहुंचे और उनसे अपने अनुभव साझा किए।

हाईकोर्ट के कॉरिडोर से होते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा गांधी चौक पहुंचे। यहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित दर्जनों वकीलों ने माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया और आगामी जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान हाईकोर्ट मुंशी संघ ने भी जस्टिस शर्मा का सम्मान किया।

CMYK

⊕

⊕

⊕

CMYK



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सेवा संकल्प अभियान — जन सेवा ही प्रभु सेवा

(17 सितम्बर-17 अक्टूबर 2026)

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूमबर,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

**₹924 करोड़ के 1,452 विकास कार्यों का
शिलान्यास एवं लोकार्पण**

मुख्य अतिथि

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री



जनजाति विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक

जनजातीय आस्था के प्रमुख केंद्र बेणेश्वर में लगभग ₹ 180 करोड़ की लागत से विकास कार्य

पीएम कुसुम योजना में ₹ 30 करोड़ व्यय कर 4,312 जनजाति कृषकों के लिए सोलर पंप स्थापित

अनुसूचित/सहरिया क्षेत्र के 25.09 लाख जनजाति कृषकों को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट वितरित

डूंगरपुर में शिल्पग्राम का हो रहा निर्माण



26 सितम्बर, 2026 | दोपहर 12:30 बजे | दशहरा मैदान, प्रतापगढ़

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

#ARCHEOLOGY

The Hindu in Ancient History

How Bagore in Madhya Pradesh proves that Hinduism existed long before recorded history



When tracing the history of Hinduism, Madhya Pradesh offers several archaeological and cultural landmarks that attest to the religion's ancient origins. Among these is Bagore, a site in Madhya Pradesh whose historical and religious significance provides compelling proof that Hinduism has thrived in the region for thousands of years, long before many other recorded histories.

What is Bagore?

Bagore is a lesser-known archaeological and historical site located in Madhya Pradesh, home to remnants of ancient temples, sculptures, and inscriptions. These relics, dating back several centuries and sometimes millennia, showcase early Hindu religious practices, art, and architecture.

Archaeological Evidence of Early Hinduism

- Temple ruins with characteristic Hindu architectural styles such as *shikhara* (temple towers) and *mandapa* (pillared halls).
 - Sculptures and carvings depicting Hindu deities like Shiva, Vishnu, and various manifestations of the Goddess (Devi), which provide clear iconographic proof of worship.
 - Inscriptions in ancient scripts such as Brahmi and Gupta scripts that mention Hindu rituals, patronage by kings, and references to Vedic deities.
- These findings date back to periods well before many external influences arrived in the subcontinent, underscoring that Hinduism was an established and thriving religion in central India long ago.

Historical Context

Madhya Pradesh, often called the "heart of India," has been a crucible for Hindu thought, art, and culture. The Bagore site fits within a broader historical narrative.

- The Gupta Empire (4th to 6th century CE), considered a golden age of Hindu culture, left extensive religious and artistic legacies in the region.
- Many Hindu temples and inscriptions found in Madhya Pradesh predate the arrival of major Islamic rulers or colonial powers, illustrating Hinduism's deep roots.
- The persistence of Hindu worship practices at Bagore also reflects the continuous cultural traditions carried forward through local communities.

Why Bagore Matters

While grander sites like Khajuraho often dominate discussions about ancient Hinduism in Madhya Pradesh, places like Bagore provide critical grassroots evidence. They show that Hinduism was not only a religion of kings and grand temples but also a living faith practiced by local populations across centuries. This challenges any notion that Hinduism's presence is a recent development or solely linked to well-known monumental sites. Instead, Bagore highlights a continuous, thriving tradition of Hindu worship and culture long before many historical events that shaped the subcontinent.



A John Trumbull painting of George Washington's capture of Hessian soldiers in Trenton, New Jersey, in December 1776.

• Verna Mohan

On August 15, 1776, a flotilla of British ships arrived on Staten Island, New York, just south of Manhattan. On board, the vessels were more than 8,600 foreign soldiers, the first major contingent of German troops to reach the American Colonies. (Another group had set up camp in Quebec several months earlier to reinforce British forces in Canada.)

There was no mistaking the new arrivals. Unlike their British allies, who were famously known as the redcoats, the Hessians usually wore blue or green coats, sometimes accompanied by tall, pointy brass headgear called miter caps. For more than a year, the British Army had been battling rebellious colonists' intent on establishing an independent nation. In October 1775, a fed-up George III announced his intention to "put a speedy end to these disorders by the most decisive exertions."

The British king added that he had "received the most friendly offers of foreign assistance." Despite vigorous objections from some lawmakers, Parliament backed George in taking up those offers, expecting that the added manpower would soon crush the rebellion once and for all.

The Hessians apparently shared that optimism. "None of the soldiers that went to America in 1776 anticipated that the war would last more than a year or two," writes Frederike Baer, a historian at Penn State Abington College, in her 2022

book, *Hessians: German Soldiers in the American Revolutionary War*. In fact, both the British and the Germans had seriously underestimated the Americans' resolve. The war would drag on for another seven years before finally ending with the Treaty of Paris in September 1783. By then, some 30,000 Germans had been called on to serve. Thousands died in combat or succumbed to disease. And the British went home in defeat.

The Hessians?

The soldiers commonly referred to as Hessian mercenaries weren't mercenaries by the strict definition of the term. They hadn't hired themselves out individually as fighters but were instead on loan from their rulers, who received cash subsidies from Great Britain in exchange for their service. Some of the soldiers had volunteered, others were drafted and still others were essentially grabbed off the streets and pressed into service.

These men weren't all Hessians, either. Germany, at the time, was not a unified nation but rather a collection of territories that had once been a part of the Holy Roman Empire, each governed by its own ruler. Britain signed subsidy treaties with six of them, including Hesse-Cassel and Hesse-Hanau, whose soldiers represented the true source of the mercenaries.

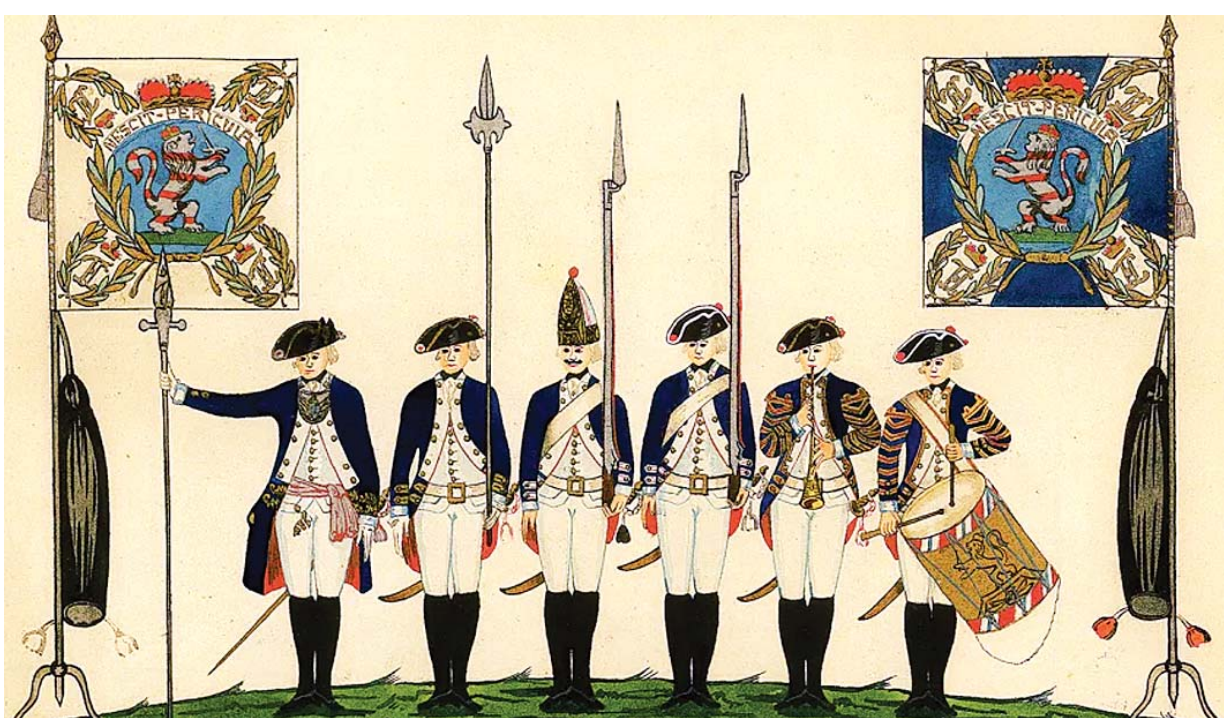
Subsidy treaties had a long tradition in Europe, dating back to at least the 1400s. During the Seven Years' War, which ended in 1763, Britain had a subsidy treaty with Prussia to supply it with troops; Prussia to supply it with troops; Prussia to supply it with troops; Prussia to supply it with troops.

As it turned out, the Germans weren't the British government's first choice. Its envoys had approached Russia, only to be turned down by the empress Catherine the Great. The Dutch also balked at cooperating.

The subsidy treaties were separately negotiated with each German ruler and could differ from one to the next. Typically, the rulers agreed to supply a certain number of troops for a set amount of money that would keep flowing for the duration of the war plus another one or two years. If the British sustained losses, the ruler was responsible for replacing the dead to get back to the agreed-upon number. In some cases, German leaders would be paid extra for every soldier killed or wounded, a practice that some critics denounced as "blood money."

The soldiers themselves received their pay directly from the British. From the beginning, the Germans were demonized in ways that persisted for decades, partly as a result of patriot propaganda. To "rile up American men," as Baer puts it in an interview, they were characterized as heartless, bloodthirsty monsters. Word on the cobblestone streets of the time included rumors that Hessians were cannibals who ate babies.

Even for colonists who might have been skeptical of the rumours, the simple fact that German soldiers would fight on American soil was considered an outrage. From the Americans' point of view, it was one thing for the British to try to put down a rebellion by their own colonists. It was another for them to bring in foreigners to help finish the job.



A circa 1783 illustration of Hessian troops.

Who were the Hessians?

From the beginning, the Germans were demonized in ways that persisted for decades, partly as a result of patriot propaganda. To "rile up American men," as Baer puts it in an interview, they were characterized as heartless, bloodthirsty monsters. Word on the cobblestone streets of the time included rumours that Hessians were cannibals who ate babies.

International Rabbit Day



International Rabbit Day is celebrated to raise awareness about rabbits and promote their care, protection, and welfare. Rabbits are gentle, intelligent, and social animals that make wonderful companions when treated with kindness and respect. The day reminds us that rabbits need proper food, clean shelter, exercise, and love to live healthy lives. It also encourages people to learn about responsible pet ownership and support organizations that rescue and protect rabbits. International Rabbit Day is a great opportunity to appreciate these adorable animals and spread awareness about their needs. By caring for rabbits responsibly, we can help create a safer and happier world for them.

#AMERICAN WARS



A depiction of Hessian troops' surrender to George Washington after the Battle of Trenton.



Hessian troops (foreground) at the Battle of Bennington.

The subsidy treaties were separately negotiated with each German ruler and could differ from one to the next. Typically, the rulers agreed to supply a certain number of troops for a set amount of money that would keep flowing for the duration of the war, plus another one or two years. If the British sustained losses, the ruler was responsible for replacing the dead to get back to the agreed-upon number. In some cases, German leaders would be paid extra for every soldier killed or wounded, a practice that some critics denounced as "blood money."

As for the food, Seume wrote, "the bacon was probably four or five years old, had black stripes on both the outer edges, was yellow towards the middle." The bread was infested with worms, which the men "had to eat as a substitute for fat." The drinking water, meanwhile, "smelled like the rivers of Hades. ... One had to hold one's nose while swallowing."

By the time the ships reached New York, the men had been at sea for over three months. The Hessians disembarked on Staten Island, the Continental Congress passed a resolution aimed at persuading as many of them as possible to desert the British and take up residence in the new country.

The resolution promised that Hessians who switched sides "shall be protected in the free exercise of



A 1975 painting of the Battle of Trenton.

commander William Howe pressed them into service. On August 22, British and German troops crossed the bay between Staten Island and Long Island to begin a series of amphibious landings on the latter's western shore. They would soon number about 20,000 troops: 15,000 British and 5,000 Germans.

Five days later, this combined force attacked the Continental Army from the south as other British troops closed in from the east. The Americans were vastly outnumbered and sustained heavy losses, including the deaths of some 300 soldiers and the capture of 1,100 more, compared with just over 60 deaths on the British and German side. Washington's men retreated to Brooklyn Heights on the northern edge of Long Island. In the dead of night on August 29, the surviving Americans quietly escaped across the East River into Lower Manhattan.

Washington's troops managed to hold New York City for a time, but they abandoned it in mid-September in the face of an imminent British attack. Howe's British and German troops landed at Kips Bay on the eastern coast of Manhattan, on September 15, forcing the Continental soldiers to retreat northward. The following day, Howe's men attacked Washington's troops in Harlem Heights, on the north end of Manhattan.

The Battle of Harlem Heights provided a much-needed victory for the Continental Army's morale, but the men were soon forced to flee once more, first to White Plains in Westchester County, then

across the Hudson River into New Jersey and from there into Pennsylvania. The Americans had lost New York City and wouldn't retake it until 1783.

While the British and German forces might have seemed all but invincible at this point, that perception would soon change. On the night of December 25, 1776, Washington and his troops crossed the Delaware River from Pennsylvania to mount a surprise attack on the German garrison that had been established in Trenton, New Jersey. After a fierce two-hour battle the following day, the Germans surrendered, and close to 900 of them were taken prisoner.

The Battle of Trenton proved to be a turning point in the war, convincing the colonists that their army could more than hold its own against the enemy. Even so, the conflict would continue for the better part of a decade. And the Germans would play a part in every major military campaign of the war.

Over time, American colonists' attitudes towards the Hessians began to evolve. They were not invincible supermen but a diverse mix of professional soldiers and ordinary citizens, some fresh off the farm. Many colonists came to prefer them to the British, even sympathizing with them as innocent victims forced by money-hungry tyrants to fight a war on the other side of the Atlantic.

While estimates vary and no one can ever know for sure, it's likely that the number of Americans today with a "Hessian" or two in their family tree is somewhere in the millions. In the end, the Germans did have a major impact, just not the one George III intended.



Johann Gottfried Seume, a German man who fought for the British during the American Revolution.

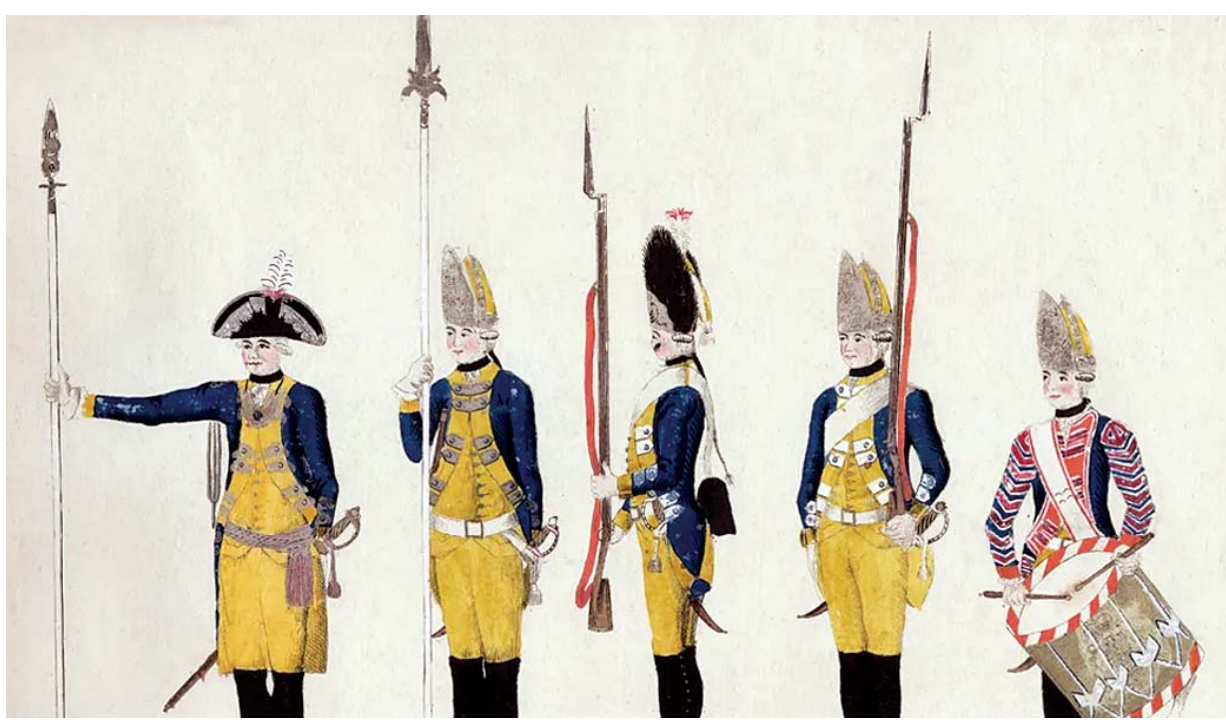
prisoners generally agree that they received much kinder treatment from them than from the British officers and soldiers."

The Hessians were still the enemy, of course, and they were far from saints. They earned a reputation for helping themselves to whatever property they wanted as rightful spoils of war. In their defense, Baer points out that plundering in wartime was a common practice, and the Germans weren't the only ones guilty of it. British troops were also known to plunder, although the army officially discouraged the practice. Rebel colonists apparently didn't hesitate to loot the homes and farms of their loyalist neighbours.

Of the roughly 30,000 Germans who participated in the conflict, Lowell estimated that just over 17,300 returned to their native lands. Approximately 1,200 were killed in the war, and nearly 6,400 died as a result of accidents or illness. The historian classified another 5,000 as deserters. Baer puts the number of Germans who stayed behind in North America at between 5,000 and 6,000. As many as 3,500 settled in the U.S., with the rest relocating to another part of the continent.

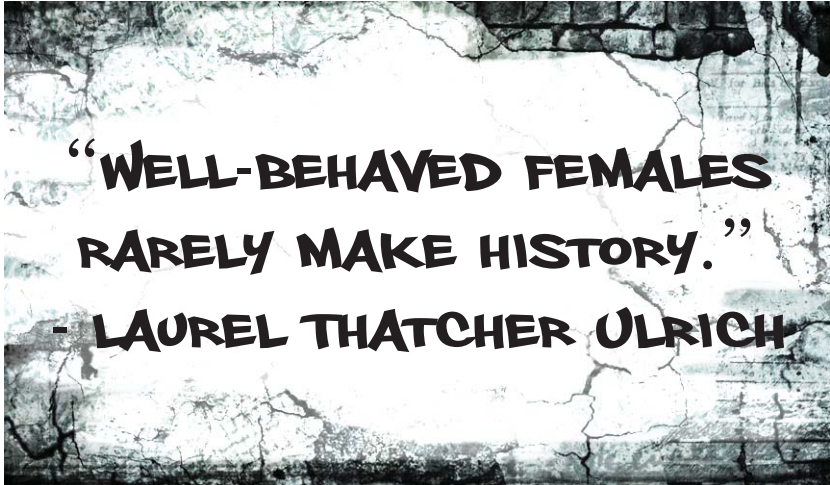
While estimates vary and no one can ever know for sure, it's likely that the number of Americans today with a "Hessian" or two in their family tree is somewhere in the millions. In the end, the Germans did have a major impact, just not the one George III intended.

rajeshsharma1049@gmail.com

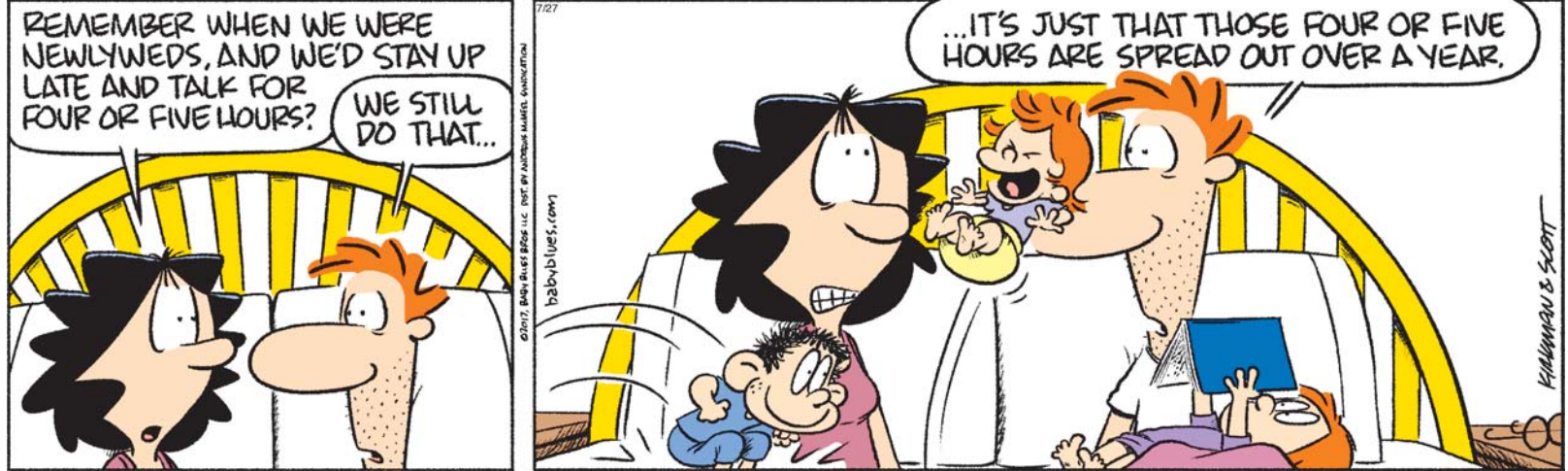


An illustration of Hessian soldiers in uniform.

THE WALL



BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

स्यालोदड़ा में प्रदूषण जांच के पहुंची टीम को क्रशर बंद मिलने पर ग्रामीणों का विरोध

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही क्रशर बंद कर दिए गए और सड़कों पर पानी का छिड़काव कर दिया

पाटन, (निसं)। ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा में कालका माता मंदिर के पास प्रदूषण की स्थिति की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग की मोबाइल वैन पहुंची। विभाग की ओर से क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच की गई, लेकिन जांच के दौरान अधिकांश क्रशर बंद मिलने पर ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे खानापूर्ति बताया।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही क्रशर बंद कर दिए गए और सड़कों पर पानी का छिड़काव कर दिया गया। इससे सामान्य दिनों में रहने वाली धूल और प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जांच में सामने नहीं आ सकी। ग्रामीणों ने जांच स्टाफ पर क्रशर संचालकों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष एवं अचानक जांच कराने की मांग की।

ग्रामीण रमेश गुर्जर ने आरोप लगाया कि प्रदूषण विभाग की गाड़ी पहुंचते ही रास्तों पर पानी का छिड़काव शुरू करवा दिया गया। साथ ही अधिकांश क्रशर भी बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि सामान्य दिनों की तरह क्रशर चलते रहते और सड़क पर पानी का



पाटन के स्यालोदड़ा में प्रदूषण नियंत्रण विभाग की मोबाइल वैन जांच के लिये पहुंची।

छिड़काव नहीं किया जाता तो प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सामने आती। ग्रामीण पंकज सैनी ने कहा कि विभाग की ओर से की जा रही जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। उन्होंने मांग की कि क्षेत्र में अचानक जांच की जाए अथवा स्थायी रूप से प्रदूषण मापने की

मशीन लगाई जाए, ताकि क्षेत्र में धूल प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी हो सके। उन्होंने कहा कि क्रशर इकाइयों से दिन-रात उड़ने वाली धूल के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सैकड़ों लोंग घूल प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं

से परेशान हैं। उनका दावा है कि क्रशर इकाइयों में काम करने वाले कई श्रमिक टीबी और सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित हुए हैं और कुछ की मौत भी हुई है।

ग्रामीण गिरवर सैनी ने सवाल उठाया कि जब क्रशर ही बंद हैं तो प्रदूषण की वास्तविक स्थिति कैसे

■ **ग्रामीणों ने जांच स्टाफ पर क्रशर संचालकों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष एवं अचानक जांच कराने की मांग की**

सामने आएगी। उन्होंने कहा कि क्रशर संचालन के दौरान जांच की जानी चाहिए, तभी क्षेत्र में धूल प्रदूषण की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। प्रदूषण नियंत्रण विभाग सीकर के आरओ नीरज शर्मा ने बताया कि जयपुर से मोबाइल मशीन एक महीने के लिए विभाग के पास आई हुई है। इसके माध्यम से जिले में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की रूटीन जांच की जा रही है। मशीन एक स्थान पर करीब 24 घंटे तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जांच औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण की जांच से अलग है। इंडस्ट्रियल प्रदूषण की जांच विभाग की अलग मशीन के माध्यम से की जाती है।

होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी

तीन साइबर ठग गिरफ्तार, पांच मोबाइल, लैपटॉप और ठगी के पैसों से खरीदी थार जब्त

■ **सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथी से होटल जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनवाते थे**

पहुंची तो यूपी नंबर की काली थार खड़ी मिली। गाड़ी में पांच युवक बैठे थे। पुलिस को देखते ही चालक और उसके पास बैठा युवक जंगल की ओर भाग निकला, जबकि पीछे की सीट पर बैठे तीन युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। पृष्ठताछ में उनकी पहचान वसीम पुत्र इदरीस, अकरम पुत्र काशीम, दोनों निवासी दौलतपुर (लहचोरा), थाना गोवर्धन, जिला मथुरा तथा तारीफ पुत्र हनीफ निवासी जोतरी पीपल, थाना गोपालगढ़, डींग के रूप में हुई। तलाशी में इनके पास से पांच मोबाइल और एक लैपटॉप मिले।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी किसी वास्तविक होटल से मिलती-जुलती फर्जी

वेबसाइट तैयार करवाते थे। इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरोपी तारीफ की मदद ली जाती थी। वेबसाइट के कॉन्टेक्ट सेक्शन में फर्जी मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर डालकर ग्राहकों को संपर्क के लिए आकर्षित किया जाता था। ग्राहक होटल बुकिंग के लिए संपर्क करता तो आरोपी व्हाट्सएप पर बातचीत कर उसे विश्वास में लेते और भुगतान के लिए फर्जी क्यूआर कोड भेजते थे। क्यूआर कोड के जरिए रकम हासिल करने के बाद ठाहक से संपर्क तोड़ देते थे।

आरोपी फर्जी आईडी के साथ फर्जी सिम व बैंक खातों का इस्तेमाल भी करते थे। पुलिस को जांच में अलग-अलग तरह के प्रलोभन देकर लोगों को ठगने के साक्ष्य भी मिले हैं। मौके से जब थार के बारे में आरोपियों ने बताया कि गाड़ी फरार आरोपी मानवेंद्र उर्फ कलुवा निवासी मुड़सेरस की है और इसे साइबर ठगी की रकम से खरीदा गया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की भी जांच कर रही है।

अजमेर हाई सिक्थोरिटी जेल में दो बंदियों ने निगरानी कैमरे तोड़े

■ **बैरक की छत पर मिले कैमरों के टूटे हिस्से, मामला दर्ज**

गई, जहां बैरक की छत पर कैमरों के टूटे हुए हिस्से मिले। जेल के नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध पुरानी रिकॉर्डिंग की जांच की गई। फुटेज में सामने आया कि सेल नंबर-3 में बंद सुमित कुमार ने निगरानी कैमरे को नुकसान पहुंचाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया। रिकॉर्डिंग में वह सेल के शौचालय की दीवार पर चढ़ता हुआ भी दिखाई दिया। जेल प्रशासन के अनुसार, 4 सितंबर की सुबह करीब 7 बजकर 15 मिनट तक सेल नंबर-3 का कैमरा काम कर रहा था। इसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इसी तरह सेल नंबर-5 में लगा कैमरा भी सुबह करीब 7 बजकर 12

अजमेर, (निसं)। अजमेर की हाई सिक्थोरिटी जेल में बंद दो बंदियों द्वारा अपने-अपने बैरक में लगे निगरानी कैमरों को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की जांच में दोनों कैमरों के टूटे हुए हिस्से बैरक के ऊपर स्थित छत से बरामद हुए। मामले में जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाईंस थाना पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके आधार पर दोनों बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 सितंबर की रात बैरक सेल नंबर 3 और सेल नंबर 5 के निगरानी कैमरे अपनी जगह पर नहीं मिले। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो दोनों कैमरे गायब थे। इसके बाद आसपास के हिस्सों की तलाशी ली

मिनट तक रिकॉर्डिंग करता दिखाई दिया। रिकॉर्डिंग में सुमित कुमार के हाथ में पत्थर दिखाई देने और उसे निगरानी कैमरे की दिशा में फेंकने की बात सामने आई है। इसके बाद दूसरा बंदी रामबीर पुत्र सत्यवीर भी सेल में आता दिखाई देता है। कुछ देर बाद सुमित कुमार शौचालय की दीवार पर चढ़कर कैमरे तक पहुंचने का प्रयास करता नजर आया। इसके बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। जेल प्रशासन ने दोनों बंदियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा प्रशासन के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर सिविल लाईंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच के साथ-साथ कैमरों की क्षतिग्रस्त करने के पीछे की वजह और दोनों बंदियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

धर्म, राजनीति और व्यक्ति के चरित्र को बदलने का औजार है पुस्तकें : प्रो. दाधीच

जयपुर /चूरू। पुस्तकें धर्म, राजनीति और व्यक्तियों का चरित्र बदलने का औजार रही हैं और वैचारिक धरातल पर आज भी उतनी ही मारक हैं। पुस्तकों के संग व्यक्ति एकांतवास में रहकर भी पूर्णता प्राप्त करता है। पुस्तकों की संगत से वह सब कुछ पा लेता है जो जीवन के सच से साक्षात्कार कराने के लिए

■ **चूरू में स्थानीय प्रयास संस्थान के प्रो. नौरत्नचंद धारीवाल को समर्पित पुस्तक उपहार कार्यक्रम का आयोजन**



चूरू बालिका महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित किया।

पर्याप्त है। यह विचार लेखक-चिंतक एवं वक्तामन महावीर खुला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. नरेश दाधीच ने शुक्रवार को चूरू बालिका महाविद्यालय सभागार में स्थानीय प्रयास संस्थान के प्रो. नौरत्नचंद धारीवाल को समर्पित पुस्तक उपहार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। प्रो. दाधीच ने कई ऐतिहासिक, राजनीतिक संदर्भों के माध्यम से कहा कि पुस्तकें समय की जरूरत हैं और खासकर युवा पीढ़ी को पुस्तकों एवं पुस्तक-संस्कृति से जुड़ना चाहिए।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और प्रो. धारीवाल के पुत्र पूर्व आईएएस सुनील धारीवाल ने कहा कि व्यक्ति का चरित्र न केवल उसके परिवार को गढ़ता है अपितु पूरे परिवेश को आंदोलित

करता है। प्रो. धारीवाल ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने संघर्ष के मार्ग से गुजरते योग्य शास्त्र को गढ़ा और एक स्वस्थ समाज निर्माण का संकल्प लिया। पूर्व आईएएस डॉ. लोकनाथ सोनी ने कहा कि पुस्तक और जिंदा व्यक्ति समाज को आगे ले जाते हैं। प्रो. धारीवाल के कारण मुझ जैसे कितने ही व्यक्ति बने और आगे बढ़े। राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट के पूर्व सदस्य प्रो. एच. आर. ईशरान ने कहा कि पुस्तकों से गहराई से जुड़े प्रो. धारीवाल की स्मृति में पुस्तक उपहार से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। प्रयास का लेखक को लागत और पाठक को पुस्तक मिशन उसी सार्थक कड़ी की मुहिम है। कार्यक्रम अध्यक्ष नगरपरिषद के पूर्व सभापति एवं महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामगोपाल बहड़ ने

कहा कि पुस्तकों से जुड़ना और प्रो. धारीवाल को याद करना दोनों ही क्षण गर्व भरे हैं।

शिक्षाविद् प्रो. नौरत्नचंद धारीवाल की जयंती पर आयोजित हुए उक्त कार्यक्रम में धारीवाल परिवार द्वारा प्रयास संस्थान के माध्यम से चूरू अंचल के लेखकों से अस्सी हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें क्रय कर महाविद्यालय के पुस्तकालय को भेंट की गईं। महाविद्यालय प्राचार्य आशा कोठारी को प्रयास संस्थान के अध्यक्ष और राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण एवं पूर्व आईएएस सुनील धारीवाल ने पुस्तकें भेंट की। अंचल के साहित्यकार अशोक अनुराग, स्नेहलता शर्मा, राजेंद्र मुसाफिर, किशोर कुमार निर्वाण,

आशीष गौतम, डॉ. बजरंग बगड़िया, मंगल व्यास भारती आदि ने अपनी पुस्तकें मंच से प्रयास को दी और ऑनलाइन मूल्य प्राप्त किया।

प्रो. धारीवाल के चित्र पर पुष्पाजलि से ग्रंथ हुए कार्यक्रम में स्वागत उद्घोषण प्रयास संस्थान के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण ने दिया और योजना के विषय में बताया। कार्यक्रम में इंजीनियर सोहनलाल फगेड़िया, एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा, संतोष मासूम, श्यामसुंदर शर्मा, के. आर. पाटवाल, सुभाष मेघवाल, अशोक कुमार डूडी, प्रो. हिमांशु महला, डॉ. कृष्णा जाखड़, श्रेयांशु धारीवाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। धन्यवाद महाविद्यालय की प्राचार्य आशा कोठारी ने दिया।

विकसित भारत-जन सेवा अभियान के तहत पक्के आवास की स्वीकृति मिली

जयपुर। किसी परिवार के लिए पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की चारदीवारी नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का भरोसा होता है। वर्षों से कच्चे और जर्जर मकान में रह रही जोधपुर जिले के डांगियावास की सुगरी पत्नी जस्सा राम के लिए यह सपना अब वास्तविकता में बदलने को है। विकसित

■ **शिविर में गोरधन राम के लिए भी वर्षों पुरानी समस्या के समाधान का रास्ता खुला**



जन सेवा शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में सुगरी को लाभ मिला।

ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएँ उपलब्ध होने से ग्रामीणों की संबंधित कार्यालयों तक जाने की परेशानी कम हुई और मौके पर ही प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की गई। इसी शिविर में गोरधन राम पुत्र कंवराराम के लिए भी वर्षों पुरानी समस्या के समाधान का रास्ता खुला। उनके खसरा संख्या 172 एवं 180 के हिस्से में दर्ज अशुद्धि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक प्रपत्र तैयार कर मौके पर ही शुद्धीकरण की कार्यवाही की गई।

एक और सुगरी को सुरक्षित आवास की दिशा में कदम मिला, तो दूसरी ओर गोरधन राम को भूमि अधिलेख से जुड़ी समस्या से राहत मिली। उल्लेखनीय है कि भजनलाल

सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित विकसित भारत-जन सेवा अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न गतिविधियों के साथ सेवा सेतु शिविरों का आयोजन कर रही है। अभियान का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने, पात्र लोगों को योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर लंबित प्रकरणों एवं परिवेदनाओं के निस्तारण को गति देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अभियान में विभागों के समन्वय और सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अलवर के जिला अस्पताल में मरीज की मौत

अलवर, (निसं)। अलवर के जिला अस्पताल में गुरुवार रात मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इयूटी डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि तबीयत बिगड़ने के दौरान बार-बार मदद मांगने के बावजूद मरीज को समय पर उपचार नहीं मिला।

जानकारी के अनुसार दीवान जी का बाग निवासी निर्मल को पिछले तीन दिनों से बुखार था। गुरुवार शाम अचानक तबीयत त्र्यंदा खराब होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां जांच के बाद उसे मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि वार्ड में मरीज को देखने पहुंचे डॉक्टर के कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे। उनका कहना है कि डॉक्टर ने मरीज को ठीक से नहीं देखा और इंजेक्शन लगाने के बाद वहां से चले गए। कुछ देर बाद मरीज की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद परिजन वार्ड में मौजूद स्टाफ से मरीज को संपालने और इलाज करने की लगातार गुहार लगाते रहे। परिजनों के मुताबिक, मरीज की हालत बिगड़ने के दौरान भी समय पर पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं मिली। इसी दौरान परिजनों ने घटनाक्रम को वीडियो बनाया शुरू कर दिया। आरोप है कि वार्ड में मौजूद एक स्टाफकर्मी ने उन्हें धमकाया और मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया।

तिरंगा योजना को आठ साल बीतने के बाद भी भरतपुर स्टेशन पर नहीं लहराया तिरंगा

भी भरतपुर स्टेशन पर नहीं लहराया तिरंगा

भरतपुर के आसपास के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 100 फीट या बड़े राष्ट्रीय ध्वज पहले से लगाए जा चुके हैं

■ **रेलवे स्टेशन के बाहर वर्षों से तिरंगे का पोल खाली खड़ा रहना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है**

■ **रेलवे की ओर से प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगाने की पहल वर्ष 2018 में शुरू की गई थी**

सामान्य रेलवे स्टेशन नहीं है। यह संभाग मुख्यालय होने के साथ-साथ क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र है। इसके बावजूद स्टेशन के बाहर वर्षों से तिरंगे का पोल खाली खड़ा रहना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है।

मदेरणा ने कहा कि भरतपुर देश-विदेश के पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ने वाले लोकप्रिय गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन सर्किट में भी भरतपुर का महत्वपूर्ण स्थान है। रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले विदेशी

पर्यटकों के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटक और भरतपुर से बाहर काम करने वाले स्थानीय लोग भी स्टेशन से गुजरते हैं। ऐसे में स्टेशन पर तैयार 100 फीट का पोल लेकिन उस पर तिरंगे का ना होना लोगों को खटकता है।

मदेरणा ने बताया कि रेलवे की ओर से प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इसके पीछे सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रमुखता देना और यात्रियों में राष्ट्रीय

भरतपुर निवासी राहुल मदेरणा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भरतपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर तिरंगे के लिए पोल और फाउंडेशन तैयार होने के बावजूद वर्षों तक उस पर झंडा नहीं लगाया चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य रेलवे और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। ताकि वर्षों से अधूरा पड़ा यह काम पूरा हो और भरतपुर रेलवे स्टेशन के बाहर भी राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ लहराता दिखाई दे। उनकी मांग है कि रेलवे इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूरा करे और भरतपुर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए।

नितिन नबीन व भजनलाल ने पंचायतों के लिये 60 प्रचार रथ खाना किये

पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सेवा संकल्प सभा में जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधा सम्पर्क रखने की सीख दी

जयपुर, 25 सितंबर। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली सफलता के बाद अब पार्टी ने आगामी पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर जयपुर के दादिया में आयोजित

■ सेवा संकल्प सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिये 2636 करोड़ रुपये के निकाय कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया।



जयपुर के दादिया में आयोजित सेवा संकल्प सभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया।

“सेवा संकल्प सभा” में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठी ने कार्यकर्ताओं एवं नवनिर्वाचित निकाय जनप्रतिनिधियों को जनसेवा का मंत्र देते हुए पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसी कार्यक्रम के दौरान 90 प्रचार रथों को पंचायतों के लिए खाना किया गया। इन रथों के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास

कार्यों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में विधायक, सांसद तथा निकाय एवं पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उनका जनता से सीधा संपर्क होता है। श्री-टियर सिस्टम के जनप्रतिनिधि ही सरकार की

योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता के सुख-दुख में भागीदार बनना ही जनप्रतिनिधि की सार्थकता है। मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश देते हुए कहा कि सरकार के विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए।

सेवा संकल्प सभा के दौरान राज्यसभा सांसद नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 2636 करोड़ रुपए के 929 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसी कार्यक्रम में, विभिन्न योजनाओं के 36 लाख लाभार्थियों के खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

जयपुर, जोधपुर, कोटा में भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से बीकानेर ही एकमात्र ऐसा नगर निगम है, जहां पर कांग्रेस के महापौर बने हैं, बाकी 9 जगहों पर भाजपा के महापौर बने हैं। ज्ञात रहे कि गत 21 सितंबर को प्रदेश के 7 नगर निगम सहित, 303 निकायों में मेयर, चेयरमैन और अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इन 7 नगर निगमों में से उदयपुर, अजमेर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर में भाजपा के मेयर

बने थे। शुक्रवार को जयपुर के महापौर चुनाव में भाजपा के सुनील कोठारी की 89 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर को 60 वोट मिले। एक पार्श्व ने नोटा का चुनाव किया। यहां कुल 150 वार्ड हैं। इसी प्रकार, जोधपुर महापौर चुनाव में भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता को 53 वोट मिले, उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार राजेन्द्र सोलंकी को 47 मत मिले। यहां कुल 100 वार्ड हैं।

इसी तरह, कोटा नगर निगम के महापौर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अनुसुइया गोस्वामी को 65 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को सिर्फ 35 मत मिले। यहां 100 वार्डों में कांग्रेस के 39 पार्श्व हैं, और भाजपा के 57 व 4 निर्दलीय हैं। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ 35 वोट मिलना साफ जाहिर करता है कि यहां कांग्रेस के 4 पार्श्वों ने क्रॉस वोटिंग की है।

ज्ञानेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। कुछ कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त की भूतान यात्रा के कारण भी स्थगित किए गए थे। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एक दौर पर 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं, सुर्जों ने कहा कि यह खर्च केवल तब होता है जब कोई कार्यक्रम वास्तव में आयोजित किया जाता है।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इसके बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:05 बजे राजकीय महाविद्यालय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रतापगढ़ के कार्यक्रमों के बाद, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए खाना होंगे। शाम 4 बजे वे रफिस रिजॉर्ट, उदयपुर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम को जयपुर लौट आएंगे।

कोचिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) और पूर्व अतिरिक्त इनकम टैक्स कमिश्नर होने का हवाला देते हुए बड़े बदमाशों से संपर्क होने की बात भी कही। शिकायत में आरोप है कि डागुर ने यह भी धमकी दी कि तीनों को इस तरह मरवाया जाएगा कि उनके परिजन भी पहचान नहीं पाएंगे।

ज्ञानेश कुमार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की ओर ध्यान दिलाया। घोष ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस समय भारत में जो हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से व्यवस्थित तरीके से हटाने के लिए किया गया है। लेकिन भारत की जी इस बात को समझ गई है और अब स्थिति बदल रही है। एक अन्य समानान्तर घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर, दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना, लिए गए फैसलों, जारी दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा अधिवक्ता चांद कुरेशी के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि ऐसे फैसलों को असंवैधानिक, मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों से बाहर और अमान्य घोषित किया जाए। एक अन्य अधिवक्ता, बृजेश सिंह ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना के लिए सीईसी कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की वैधानिक अनुमति मांगी।

ज्ञानेश कुमार और उनके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जोड़ना, नाम हटाना और फिर बहाल करना, फॉर्म 6 में बदलाव, अपील दाखिल करना तथा मतदाता डेटाबेस और आईटी सिस्टम का केन्द्रीयकरण शामिल था। एक नोट में संघू ने कुछ कार्रवाहियों को “अनधिकृत और गैरकानूनी” बताया। दोनों चुनाव आयुक्तों ने काम के बंटवारे में किए गए ऐसे बदलावों को लेकर कैबिनेट सचिव को भी अलग-अलग पत्र लिखे, जिससे मतदाता सूची टैक्नोलॉजी पर उनकी निगरानी कम हो गई थी। ईसीआई का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और अलग-अलग राय होना विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। एक अन्य विवाद ने भी और अधिक ध्यान खींचा है। ज्ञानेश कुमार की बेटी और नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम को लेकर नए सवाल उठे हैं।

वकीलों के एक संगठन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मेधा रूपम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में “बारी से पहले” (आउट-ऑफ -टर्न) लिस्ट किए जाने (सुनवाई सूची में शामिल करने) पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा एवं ऐक्टिविस्ट आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (नैशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने रूपम और अन्य अधिकारियों के वेतन से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूलने का आदेश दिया था और उनके आचरण की कड़ी आलोचना की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस वसूली के आदेश पर रोक लगा दी। आलोचकों ने इस प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके रिश्ते का उल्लेख किया है। इस बीच, विपक्षी

नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के महाभियोग की मांग और तेज कर दी है। आंतरिक आपत्तियों का हवाला देते हुए और “एक व्यक्ति के तानाशाहीपूर्ण नियंत्रण” का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, डैरेक ओ’ब्रायन, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल सहित, कई नेताओं ने उन्हें हटाने की मांग की है। कुछ नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी और हाल के चुनावों को रद्द करने की भी मांग की है। अप्रैल में राज्यसभा के 73 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस, जिसमें “साबित कदाचार” के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की गई थी, अभी लंबित है। विपक्ष एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। ईसीआई लगातार अपनी प्रक्रियाओं का बचाव कर रहा है, लेकिन इन सभी विवादों के एक साथ सामने आने से, संस्था (चुनाव आयोग) की विश्वसनीयता को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं।

अमेरिका के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चुकानी होगी। सी ई ए ने कहा कि जियोपॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते संबंधों ने वैश्विक आर्थिक वातावरण को बुनियादी रूप से बदल दिया है। आपूर्ति में व्यवधान, व्यापार प्रतिबंध और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियां नीति-निर्माताओं के लिए लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। नागेश्वरन ने कहा कि नीति-निर्माताओं को 1980 से 2020 के दौर में हावी रहे आर्थिक नीति, ढांचे के आगे बढ़ने की जरूरत है, जब मांग प्रबंधन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता था। उन्होंने कहा, अब यह मांग प्रबंधन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह आपूर्ति प्रबंधन का मामला है। उन्होंने वैश्विक व्यापार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े उत्पादों के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि व्यापार का इस्तेमाल अब तेजी से रणनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। नागेश्वरन ने कहा, व्यापार को हथियार बना दिया गया है, कुछ मामलों में विकल्प न होने के कारण प्रतिक्रिया के रूप में और कुछ मामलों में आक्रामक आधार पर।

सी ई ए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने तत्काल तीन चुनौतियों की पहचान की-अमेरिका के साथ भारत के अस्थिर संबंध, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलाव और ए आई इकोसिस्टम में भारत की अपेक्षाकृत सीमित मौजूदगी। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि ए आई इकोसिस्टम में भारत की कोई भूमिका नहीं है, बस बौद्धिक संपदा अभी उतनी नहीं है। यह वास्तविक समस्या है, लेकिन यह आगे। उन्होंने कहा कि यह मानकर नहीं चला जा सकता कि वैश्विक बाजार हमेशा जरूरी वस्तुओं और इनपुट तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको खुद उत्पादन करना होगा क्योंकि दुनिया आपको आपूर्ति नहीं करेगी। उनकी टिप्पणियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि भारत के लिए घरेलू उत्पादन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और रणनीतिक विविधीकरण का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि देश तेजी से विभाजित होते वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच आगे बढ़ रहा है। नागेश्वरन की यह स्वीकारोक्ति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो चुका है और मामला निपट गया है तथा वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी बाजार में भारत को उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिए जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

TRUE VALUE

खरीदे प्री-ओन्ड गाड़ी 1 साल तक की वारंटी* के साथ, सिर्फ TRUE VALUE पर

CELEBRATING 60Lakh+ STORIES OF TRUST

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

TRUE VALUE CERTIFIED

JAIPUR: E-101, ROAD NO. 8, VKIA AREA, JAIPUR, PREM MOTORS: 8058791634, 8058794187, 8058794102, 8058794177 | CHITRAKOOT MARG, SATYA COLONY, TAGORE NAGAR, JAIPUR, AURIC MOTORS: 8690988784, 8890988912, 8690988758 | E-197(A), RIICO INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPUR, KP AUTOMOTIVES: 9549651769, 9116190346 | B 1 GOVIND MARG, RAJAPARK OPP. PINK SQUARE MALL, KP AUTOMOTIVE: 9549851770, 9116190344 | A-209, RAJENDRA PRASAD NAGAR, 200FT BYPASS, AJMER ROAD, JAIPUR, SATNAM MOTOCORP: 7413900007, 7413900009, 7821823626, 8290654400, 7568249500, 9358868371 | 13 JHOTWARA INDUSTRIAL AREA, NEAR JHOTWARA POLICE STATION, JAIPUR, KTL: 7412068475, 7412077170 | SECTOR-35, PRATAP NAGER, TONK ROAD, JAIPUR, SANGA AUTONATION PVT LTD.: 9057809180 | PADMAWATI COLONY- II, OPPOSITE METRO PILLAR NO 25, MANSAROVER METRO STATION JAIPUR, VIPUL MOTORS PVT. LTD.: 9829333522, 9829351470, 9079191348 | ALWAR: NEAR ALWAR PUBLIC SCHOOL, JAIPUR ROAD, ALWAR, MG MOTORS: 7240012934, 7728892248, 7073130666 | OPPOSITE MATILA POLICE STATION ALWAR BYPASS ROAD BHIWADI, FORTUNE CARS: 8875001550, 9214094335 | MANHAR VILLA, NEAR JAIL CIRCLE, VIJAY NAGAR ROAD, ALWAR, FORTUNE CARS: 7230029310, 7230029304.

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल True Value प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है। रचनात्मक चित्रण। छवियों का इस्तेमाल केवल उदाहरण मात्र है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वरुण प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिपिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा | आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdutr@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलयाया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2404100, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-भूरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रियल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय:-एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●